S.No.	Name of State/Union Territories	Whether CAD Authorities	
		Constituted	Not Constituted
20.	Tamil Nadu	—	Not constituted #
21.	Tripura	—	Not constituted #
22.	Uttar Pradesh	Constituted	—
23.	West Bengal	Constituted	—
	UNION TERRITORIES		
1.	Dadra and Nagar Haveli	—	Not constituted* #
2.	Daman and Diu	—	Not constituted* #

* Work is being implemented by Gujarat Government under Damanganga Project.

CAD Authorities not constituted and the Programme is implemented by the concerned Departments of the

Project under National Water Management Programme in Orissa

2775. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether projects under the National Water Management Programme are under implementation in orissa;

(b) if so, the details thereof alongwith project cost;

(c) the acres of land likely to be irrigated thereafter; and

(d) the details of the objectives of the above programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) to (d) No, Sir. The Would Bank assisted National Water Management Project (NWMP) has closed on March 31, 1995. The project objective was to increase agricultural productivity and farm incomes through the provision of more reliable, predictable and equitable service. Eight schemes of Orissa state covering a Culturable Command Area of 1.07 lakh hectares were taken up for implementation under NWMP at an estimated cost of Rs. 34.43 crore. However, none of the schemes could be completed during the project duration.

ए० आई० बी० पी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को ऋण

2776. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1998-99 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ए० आई० बी० पी० योजना के अन्तर्गत दस परियोजनाओं हेतु 168 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब तक 93 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति दी जा चुकी है और 46.58 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो गयी है;

(ग) शेष 75 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकार न करने के क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इस योजना की स्वीकृत राशि को व्यपगत (लैप्स) होने से छूट प्रदान करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान 153.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता स्वीकृत की गई थी जिसमें से केवल 78.00 करोड़ रुपये जारी किए गए क्योंकि राज्य सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान समय से उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। राज्य ने वर्ष 1998-99 के दौरान अपनी 10 परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 168.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। इन परियोजनाओं में 5 नई परियोजनाएं थीं और वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त कर चुकी लखवर व्यासी इसमें

शामिल नहीं की गई थी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानकों के अनुसार इन 5 नई परियोजनाओं में से केवल दो परियोजनाएं ही ऋण प्राप्त करने की पात्र थीं। अतः राज्य को 93.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता पहले ही इस कार्यक्रम में शामिल की गई 5 चालू परियोजनाओं के लिए अनुमोदित की गई थी, इसके विपरीत 76.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। 16.50 करोड़ रुपये की शेष राशि जारी नहीं की जा सकी चूंकि राज्य ने 198-99 के दौरान बराबर-बराबर का खर्च नहीं किया था और वह धनराशि समाप्त हो गयी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानकों के अनुसार राज्य सरकारों को अधिक परियोजनाओं पर थोड़े-थोड़े संसाधन खर्च करने की बजाए कम परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सरदार सरोवर परियोजना की बढ़ती निर्माण लागत

2777. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना की वास्तविक अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या सिकी मूलभूत अपेक्षित निर्माण-लागत अधिकतम हो गई है और वर्तमान में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान सरकारों के बीच मतभेद होने और तालमेल के अभाव के कारण इस परियोजना को पूरा करना असंभव हो गया है; और

कृषि मंत्रालय में रज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं॰ 314/94 में 18 फरवरी, 1999 को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें सरदार सरोवर बांध की सुरक्षा के लिए अपेक्षित हम्पों को छोड़कर बांध की ऊंचाई ई॰एल॰ 85 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दी गई। गुजरात सरकार ने तदनुसार 19 फरवरी, 1999 से सरदार सरोवर बांध पर कार्य शुरू कर दिया है।

(ख) सरदार सरोवर परियोजना पर निर्माण कार्य 6,406.04 करोड़ रुपये को अनुमोदित अनुमानित लागत (1986-87) के मूल्य स्तर पर) से 24 अप्रैल, 1987 को शुरू किया गया था और परियोजना का संशोधित आंकलन गुजरात सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। परियोजना को निधियों के मुख्य स्त्रोत गुजरात सरकार द्वारा किया गया बजटीय प्रावधान गुजरात सरकार द्वारा किए गए खर्च के विरूद्ध नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार निर्धारित भागीदार राज्यों से प्राप्त सरकार / सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा निधिया जुटाना है। इस परियोजना को विश्व बैंक ऋण के बकाया शेष के स्थान पर भारत सरकार से केन्द्रीय ऋण सहायता और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अंतर्गत सहायता भी प्राप्त हो रही है।

(ग) और (घ) परियोजना को सन् 2000 तक पूरा किया जाना था। तथापि, परियोजना का पूरा होना उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित रिट याचिका के निपटान, निधियों की उपलब्धता और नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार पक्षकार राज्यों द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एंव पुनर्स्थापना उपायों के समरूप कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने बां को अधिकतम ऊंचाई के बारे में कुछ आपत्तियां कीं और 10.3.99 को उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया और इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन है। तथापि, नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट के प्रेम वर्क के अंदर ही मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

Activitgies of Brahmaputra Board

2778. SHRI PARAG CHALIHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of activities of the Brahmaputra during the preceding three years; and

(b) details of amounts sanctioned and utilised during the said period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) During the years 1996-97, 1997-98 and 1998-99 Brahmaputra Board has completed two main Master Plans for Brahmaputra and Barak and its tributaries. These Master plans were approved by he Union Government in July, 1997. Apart from this, the Board has taken up preparation of Detailed Project Reports for 17 multipurpose projects, survey and